एलआईसी के पास 881 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड मनी

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

नई दिल्ली, 22 दिसंबर – भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 880.93 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड मैच्योरिटी की रकम थी. सरकारी जानकारी के मुताबिक कुल 372,282 पॉलिसीधारकों ने अपने मैच्योरिटी बेनिफिट को क्लेम नहीं किया है यानी पॉलिसी मैच्योर होने के 3 साल बाद भी किसी ने उस पर दावा नहीं किया है.ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने की पॉलिसी ली थी, जो मैच्योर हो गई है लेकिन उसका पैसा नहीं मिला है. ऐसे में आप उस पॉलिसी की रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं.नियमों के मुताबिक जिन पॉलिसी की मैच्योरिटी की रकम पर किसी ने क्लेम नहीं किया है उसे अनक्लेम्ड खाते में डाल दिया जाता है. रकम 10 साल तक अनक्लेम्ड रहती है तो उसे वरिष्ठ नागरिक कल्याण फंड में डाल दिया जाता है. यह पैसा बुजुर्गों की देखभाल में खर्च किया जाता हैं.

अनक्लेम्ड जमाराशि का दावा कैसे करें? : किसी भी एलआईसी दफ्तर से क्लेम फॉर्म प्राप्त करें या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें. फॉर्म भरने के बाद पॉलिसी दस्तावेज, प्रीमियम रसीदें और यदि लागू हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें. पूरा भरा हुआ फॉर्म दस्तावेजों के साथ छक्ठ दफ्तर में जमा करें. एलआईसी आपके दावे की समीक्षा करेगी और स्वीकृत होने पर, वह आपकी अनक्लेम्ड रकम राशि जारी कर देगी.

25 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एलआईसी की पॉलिसी : 1956 तक भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम करती थीं. 1 सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी एलआईसी, की शुरूआत की. अभी 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एलआईसी की पॉलिसी है.

बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स अब बैन होंगे

सरकार ने ड्राफ्ट-बिल पेश किया, उल्लंघन पर 1 करोड़ जुमार्ना और 10 साल की जेल

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

नई दिल्ली, 22 दिसंबर – केंद्र सरकार बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने का प्लान बना रही है. इस प्लान को लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है. इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन ऐप्स को बैन करने की बात कही है. इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का भी प्रस्ताव रखा गया है.बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल लेंडिंग पर काम करने वाले ग्रुप की नवंबर 2021 की रिपोर्ट में ये उपाय पहली बार सुझाए गए थे.

सरकार के ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य : केंद्र सरकार के इस ड्राफ्ट बिल का टाइटल- बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज है. इस बिल का उद्देश्य आरबीआई या किसी अन्य रेगुलेटरी बॉडीज से परमिशन लिए बिना लोगों को लोन देने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को बैन करना है.

सरकार के ड्राफ्ट बिल से जुड़ी खास बातें

▸▸ डिजिटल लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी इस बिल में शामिल

किया गया है. अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से लोन नहीं दे सकते.

▸▸ अनऑथराइज्ड लोन देने पर 7 से 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक का जुमार्ना हो सकता है.

▸▸ वहीं अगर लोन देने वाले बलपूर्वक वसूली के तरीके अपनाते हैं, तो उन्हें 3 से 10 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी.

▸▸ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े या बड़ी राशि के मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

▸▸ धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स चिंता का विषय

यह बिल ऐसे समय आया है, जब धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स अपने बलपूर्वक वसूली के तरीकों, अत्यधिक ब्याज दरों और हिडन फीस के कारण चिंता का विषय बन गए हैं.

गूगल ने प्ले स्टोर से 2,200 से ज्यादा ऐप्स हटाए

ऐसे लोन ऐप्स के दबाव के चलते कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं. इस वजह से गूगल ने सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच प्ले स्टोर से ऐसे 2,200 से ज्यादा ऐप्स हटा दिए

अक्टूबर से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब

दरों को घटाने की जरूरत, आरबीआई एमपीसी के सदस्य बोले, महंगाई के साथ वृद्धि पर हो जोर

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

नई दिल्ली, 22 दिसंबर – दो साल से रेपो दर को यथावत रखे जाने के बाद अब इसमें कटौती की वकालत होने लगी है. आरबीआई मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के सदस्य नागेश कुमार ने कहा, देश में आर्थिक मंदी इस हद तक गंभीर हो गई है, जिस पर तुरंत नीतिगत ध्यान देने की जरूरत है. दिसंबर की

एमपीसी बैठक में कुमार ने रेपो दर में 0.25 फीसदी कटौती की वकालत की थी. एमपीसी की अगली बैठक 5 से 7 फरवरी, 2025 को होनी है. एमपीसी के ब्योरे में कुमार ने घटती वृद्धि और महंगाई संबंधी चिंताओं की दोहरी चुनौतियों को दूर करने की जरूरत बताई. उनके मुताबिक, एमपीसी की अक्तूबर की बैठक के बाद से आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है. 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी विकास दर उसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत और 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई है.

गिरावट अपेक्षा से ज्यादा तेज : नागेश कुमार ने कहा, यह गिरावट अपेक्षा से अधिक तेज है और इसने वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूवार्नुमानों में व्यापक कटौती करवा दी है. रेपो में 0.25 फीसदी की कटौती महंगाई को बढ़ाए बिना आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकती है.

मुंबई बोट हादसे के तीन दिन बाद मिला लापता बच्चे का शव

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

मुंबई, 22 दिसंबर – नाव हादसे के बाद समुद्र में लापता हुए सात वर्षीय बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि तीन दिन के तलाशी अभियान के बाद शनिवार सुबह नौसेना की पोतों ने जोहान मोहम्मद निसार अहमद पठान का शव खोज निकाला. इसी के साथ दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई.

कर्ज में डूबते जा रहे देश के किसान परिवार

आय में 57 प्रतिशत बढ़त, फिर भी उधारी और खर्चों के बोझ तले दबे

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

नई दिल्ली, 22 दिसंबर– भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति में हाल के कुछ सालों में कई बदलाव आए हैं. संसद की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश में किसानों की आय तो बढ़ी है, लेकिन उनका खर्च उससे भी ज्यादा बढ़ गया है. इसका मतलब यह है कि हालांकि उनकी आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन खर्च इतना ज्यादा हो गया है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं. इस वजह से, किसान परिवारों को अपना खर्च पूरा करने के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है.

आय में वृद्धि, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ा : नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) द्वारा 2022-23 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह जानकारी सामने आई है कि पिछले पांच सालों में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में काफी वृद्धि हुई है. साल 2016-17 में जहां एक ग्रामीण परिवार की औसत मासिक आय 8,059 रुपये थी, वह 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपये तक पहुंच गई. इस आंकड़े के अनुसार, आय में 57.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यह किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखता है.

लेकिन, यही कहानी का सिर्फ एक पक्ष है. सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि इसी पांच साल की अवधि में इन परिवारों के खर्च में कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई है.

रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक खर्च 6,646 रुपये से बढ़कर 11,262 रुपये हो गया, यानी इसमें 69.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसका मतलब है कि इन सालों में खर्च में जो बढ़ोतरी हुई है, वह आय से ज्यादा है.

उधारी का बढ़ता दबाव : रिपोर्ट के अनुसार, 2016-17 और 2021-22 के बीच लोन लेने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 47.4 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया है. इसका मतलब यह है कि लगभग आधे से ज्यादा ग्रामीण परिवार कर्ज पर निर्भर हैं, और उनमें से अधिकतर कृषि परिवार हैं. कर्ज लेने की इस बढ़ती प्रवृत्ति का एक प्रमुख कारण किसानों का बढ़ता खर्च और उनकी आय का उस खर्च से मेल न खाना है.

किसान परिवारों को अपने कृषि कार्यों के लिए जरूरी निवेश करने, कृषि उपकरण खरीदने, उर्वरक और बीज खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है. इसके अलावा, मौसम की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाएं, और बाजार में मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण भी किसानों को अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है. इन सभी कारणों से किसानों का कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है.

चेन्नई : क्रिसमस समारोह के दौरान सांता क्लॉज की पोशाक पहने एक व्यक्ति नाचता हुआ.

राजस्व विभाग में बड़े बदलाव किए जाएंगे : बावनकुले

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

मुंबई, 22 दिसंबर – महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री का पद मिलते ही बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एक्शन मोड में आ गए हैं. उन्होंने ने कहा कि राजस्व विभाग के कारण जनता को परेशानी होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. मैं जनता सर्वोपरि की नीति के अनुसार काम करूंगा. महाराष्ट्र का राजस्व विभाग देश का सबसे अच्छा राजस्व विभाग है, ऐसी छवि स्थापित करूंगा.

महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व विभाग के पास नागरिकों के दस्तावेजों से संबंधित भी कई कार्य हैं. हम जल्द ही तलाठी कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय से सरकारी स्तर तक इन कार्यों की पेचीदगियों को कम करने के उपाय तलाशेंगे और आम लोगों को राहत देने का प्रयास करेंगे. मैं स्टाम्प ड्यूटी, मोबिलाइजेशन कमिश्नर और रेत से संबंधित नीतियों को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं. आने वाले समय में राजस्व विभाग में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

सरकार में उचित समन्वय : बहुदलीय सरकार को समझदारी से चलाना होगा. इसमें समन्वय की आवश्यकता है. महायुति में तीनों दलों के बीच तालमेल है और इसका प्रमाण विभागों के बंटवारे में देखने को मिला है. साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि हमारे नेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री पदों का वितरण करते समय दोनों उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ उचित समन्वय करके बिना किसी परेशानी के पालक मंत्री पदों का वितरण करेंगे.

जाहिर है, कुछ लोग नाखुश हैं

महाराष्ट्र में मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर बोले अजित पवार

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

मुंबई, 22 दिसंबर – महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर टिप्पणी करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि चूंकि फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या ज्यादा है और हर को एक विभाग देना है. ऐसे में कुछ लोग विभागों को लेकर खुश हैं और तो कुछ लोग नहीं हैं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर रविवार को मुंह खोला. उन्होंने मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन की सीमा को स्वीकार करते हुए कहा कि जाहिर है कि कुछ लोग इससे नाखुश हैं. एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती में एक रोड शो में हिस्सा लिया. छठवीं बार उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर बारामती एनसीपी तालुका और शहर की ओर से शारदा प्रांगण में अजित पवार का एक सार्वजनिक अभिनंदन किया गया.इस अवसर पर अजित पवार ने कहा कि चूंकि फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या ज्यादा है और हर को एक विभाग देना है. ऐसे में कुछ लोग विभागों को लेकर खुश हैं और तो कुछ लोग नहीं हैं.

उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को चुनौती दी. विधानसभा नतीजे के बाद विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, इस पर अजित पवार ने कहा कि हमने नहीं सोचा था कि जनता एकतरफा वोट करेगी. हमने कभी भी ईवीएम को दोष नहीं दिया.अजित पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद महायुति ने और अधिक मजबूती से काम करना शुरू कर दिया, लड़की बहिन योजना और किसानों के लिए बिजली माफी की वजह से महायुति को विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली.

दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा : कुछ दिन पहले बीड जिले के केज तालुका के मसजोग के सरपंच संतोष देशमुख की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस बीच शनिवार को अजित पवार मस्साजोग गए और संतोष देशमुख के परिवार से मुलाकात की. इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि इस मामले में जो भी उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी है.उन्होंने कहा कि बीड में एक ऐसी घटना घटी. इंसानियत को कलंकित कर देगी, जो भी उस घटना का मास्टरमाइंड है. उसे जाने नहीं देंगे चाहे उसकी कितनी भी पहुंच हो. हम तीनों ने बीड की घटना पर ध्यान दिया है.अजित पवार ने कहा है कि अमानवीय लोगों को फास्ट ट्रैक केस के जरिए मौत की सजा दी जाएगी. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने परभणी में हुई घटना पर भी गौर किया है. पुलिस को मामले की गहन जांच करने का भी निर्देश दिया गया है. अजित पवार ने कहा है कि बारामती में भी कई घटनाएं हो रही हैं, इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना जरूरी है.

सुकमा में पांच नक्सली गिरफ्तार

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

सुकमा, 22 दिसंबर – छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया. इनमें से दो पर चार लाख रुपये का इनाम था. पुलिस ने बताया कि मुचाकी हुंगा उर्फ जत्ती, कवासी गंगी, माडवी हिंगा और दो अन्य को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान दुलेदा गांव के जंगल के पास से दबोचा गया.

धक्का-मुक्की कांड: आज घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है क्राइम ब्रांच

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

नई दिल्ली, 22 दिसंबर – संसद में हुए धक्का-मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सोमवार को घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है. इससे पहले पुलिस ने संसद से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने की कवायद तेज कर दी है. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित क्रउ यूनिट कर रही है. धक्का-मुक्की कांड में चोटिल हुए बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे जिनका आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है.मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक रक्ळ टीम का गठन किया गया था. रक्ळ की टीम कल इस मामले में अपनी तफ्तीश शुरू कर सकती है. क्राइम ब्रांच की इस रक्ळ की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे.

एसआईटी में दो एसीपी भी हैं शामिल : इस मामले की जांच में 2 एसीपी को रक्ळ में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है. अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की क्रउ क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं.मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक रक्ळ टीम का गठन किया गया था. रक्ळ की टीम कल इस मामले में अपनी तफ्तीश शुरू कर सकती है. क्राइम ब्रांच की इस रक्ळ की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे.

एसआईटी में दो एसीपी भी हैं शामिल : इस मामले की जांच में 2 एसीपी को रक्ळ में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है. अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिकल

हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की क्रउ क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं.

बताया जा रहा है कि नई दिल्ली जिले के पार्लियामेंट थाने से अभी क्राइम ब्रांच को राहुल गांधी से जुड़े मामले की इन्वेस्टिगेशन की कॉपी अभी हैंडओवर नहीं हुई है. जल्द ही ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा. सूत्रों की मानें तो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा, जिसमें घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफी मायने रखती है.

राहुल गांधी पर लगा धक्का-मुक्की करने का आरोप : बीजेपी ने अपनी शिकायत में सीधे राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उन पर धक्का-मुक्की का आरोप लगाया है. ऐसे में प्रोटोकॉल को देखते हुए, सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद मोबाइल फुटेज, टच्छ रिपोर्ट काफी मायने रखती है. क्राइम ब्रांच की माने तो इन सबके अलावा पहले मौके पर मौजूद चश्मदीदों और घायल सांसदों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और इन सबके बाद क्राइम ब्रांच की रक्ळ राहुल गांधी को जांच के लिए नोटिस भेज सकती है.दरअसल, गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेताओं की शिकायत पर धक्का-मुक्की मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज की थी. यह घटना उस समय हुआ जब गुरुवार को ही संसद भवन के मकर द्वार के करीब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के आमने-सामने आ गए.

डॉ. देशमुख ने सीवरेज परियोजना के लिए ठोंका केस

पहले पन्ने से जारी – क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि रुकी हुई भूमिगत सीवरेज परियोजना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना पूरी नहीं हो सकेगी. इससे पहले भी डॉ. सुनील देशमुख अमरावती शहर में बेलोरा हवाई अड्डे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. उल्लेखनीय है कि सुनील देशमुख ने अपने सहयोगी वकील डॉ. प्रवीण पाटिल के साथ मिलकर जनहित याचिका के माध्यम से सरकार पर बेलोरा हवाई अड्डे को विकसित करने का दबाव बनाया था और अब यह उद्घाटन के अंतिम चरण में है.

देशमुख के प्रयास से ही मिली थी मंजूरी : कालान्तर में वर्ष 2005-06 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित लघु एवं मध्यम नगरों हेतु नगरीय अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अन्तर्गत 160 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट को राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के तृतीय सत्र में अनुमोदित किया गया. तत्कालीन राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख के प्रयासों से इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई. डॉ. सुनील देशमुख के फॉलोअप के कारण तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी ने 2008 में 141.93 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी और पहले चरण के लिए 34 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि भी वितरित की गई थी. इस योजना में एक ढांचा तैयार किया गया जिसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी 80% थी, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 10% था. प्रथम चरण में शहर जोन क्र. लालखड़ी में 5, 44 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 900 मिमी डीआईके अपलिफ्ट चैनल में 171 किमी सीवरेज, दूसरे चरण में बडनेरा झोन क्र 1 व 2 में पम्पिंग स्टेशन व उर्ध्ववाहिनी. और तीसरे चरण में अमरावती झोन क्र 1,2 व 3 में 46 किमी पाइपलाइन एमएलडी प्लांट इस पद्धति से काम मंजूर किया गया और काम की शुरूवात की गई.

वर्ष 2014 में पुनः निर्वाचित होने पर शुरू हुआ काम : दुर्भाग्यवश, 2009 में डॉ. सुनील देशमुख की विधानसभा चुनाव में हार के कारण योजना में और देरी हुई. लेकिन डॉ. सुनील देशमुख के फॉलोअप के चलते 2014 तक काम आंशिक रूप से पूरा हो गया. 2014 में पुनः निर्वाचित होने के बाद डॉ. सिंह ने फेज क्रमांक 1 के जोन क्रमांक 4 एवं 2 में अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 2015 में 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम सुनील देशमुख के प्रयासों से पूरा हुआ.

वर्ष 2017 तक, लालखड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और शहर के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत पाइपलाइनों सहित इस योजना का बुनियादी ढांचा पूरा हो चुका था. सुनील देशमुख ने इस दिशा में निर्णय लिया था और प्रयास भी किए थे. लेकिन तब तक, शहर के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत सीवरेज कार्य पूरा हो जाने से 25,000 संपत्तियों को इस संपूर्ण भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जोड़ने और अपशिष्ट जल को प्रसंस्करण के लिए लालखड़ी स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र तक पहुंचाने की उम्मीद थी. लेकिन चूंकि संपत्तियों को भूमिगत सीवर योजना से जोड़ना बहुत महंगा काम था, इसमें नागरिकों की भागीदारी भी बहुत कम थी, इसलिए प्रशासन 2016 तक केवल 750 संपत्तियों को ही जोड़ पाया. ऐसे में शासन स्तर से जानकारी दी गई कि जब तक इन सभी संपत्तियों को भूमिगत सीवर से नहीं जोड़ दिया जाता, तब तक अगले जोन में भूमिगत सीवर योजना का लेआउट स्वीकृत नहीं किया जा सकता. इन सभी परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए डॉ. सुनील देशमुख ने पुनः सरकारी स्तर पर मामले को आगे बढ़ाया और सरकार को 25,000 संपत्तियों को भूमिगत सीवर से जोड़ने तथा शेष सहायक कार्य करने के लिए मजबूर किया, जिससे 87 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई. इसमें सरकारी खर्च पर इन 25,000 संपत्तियों के कनेक्शन के लिए 59.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

संपति मालिकों पर नहीं डाला गया कोई बोझ

यह पूरे देश में एकमात्र ऐसा उदाहरण है, जहां संपत्ति मालिकों पर बिना किसी बोझ के सरकारी व्यय से इस कनेक्शन के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है. इसके लिए सरकारी स्तर पर काफी प्रयास करने पड़े. इसके लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया गया और 2019 की शुरूआत में काम शुरू हो गया. लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में सुनील देशमुख की एक और हार के कारण इस योजना को फिर से रोक दिया गया. सभी कार्य स्वीकृत होने, धनराशि स्वीकृत होने तथा ठेकेदार उपलब्ध होने के बावजूद, प्रशासन पिछले पांच वर्षों में इन 25,000 में से केवल 8,000 संपत्तियों का कनेक्शन पूरा करने में ही सफल रहा है. तब से किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तब से यह योजना रुकी हुई है. तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन और परेशानी भरी लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस योजना के लिए डॉ. सुनील देशमुख लगातार काफी प्रयास किए हैं. भूमिगत सीवरेज परियोजना पर आज तक जो काम हुआ है, वह उनके प्रयासों का ही नतीजा है. लेकिन किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने इस अवसर का उपयोग वर्तमान जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अरुचि को उजागर करने के लिए किया. इसका एक प्रमुख उदाहरण वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अमरावती शहर की सफाई व्यवस्था में हुई चूक और उसके परिणामस्वरूप शहर में उत्पन्न हुई सफाई समस्या है. लगातार पांच वर्षों तक इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखने के बाद भी इस मामले में किसी की पहल नहीं होने और अब अमरावती भूमिगत सीवरेज योजना का रुका हुआ काम कानूनी लड़ाई के बिना पूरा नहीं होने का विश्वास होने पर डॉ. सुनील देशमुख आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई है. इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक याचिका दायर की गई है जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी कार्रवाई तेज करे और सरकार को इस योजना और अन्य को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए मजबूर करे ताकि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इस योजना को लागू किया जाए.

19 साल के किशोर ने 4 साल के बच्चे को कार से कुचला

पहले पन्ने से जारी – इसके अलावा, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना से पहले ड्राइवर की गतिविधियों और ठिकाने का पता लगाया जा सके. आपको बता दें कि, आयुष अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर रहता था. उसके पिता एक मजदूर हैं. घटना के समय आयुष सड़क पर खेल रहा था. तेज रफ्तार से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह हादसा मुंबई में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुआ है. इससे पहले 9 दिसंबर को मुंबई के कुर्ला इलाके में एक अन्य सड़क दुर्घटना में सात लोगों की जान चली गई थी और 42 लोग घायल हुए थे. एक बीईएसटी बस का चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था. इस हादसे के बाद बस चालक संजय मोरे को गिरफ्तार कर उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था.

मसली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

अहमदाबाद, 22 दिसंबर – गुजरात के बनासकांठा जिले का मसली देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी 199 घरों में सौर छत का काम पूरा हो चुका है. शनिवार को एक अधिकारी ने बताया कि, पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर 800 की आबादी वाले इस गांव में यह योजना राज्य के राजस्व विभाग, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, बैंकों और सौर कंपनियों के सहयोग से लागू की गई.

यौन उत्पीड़न में प्रोफेसर को तीन साल की जेल

एजेंसी/प्रतिदिन अखबार

ठाणे, 22 दिसंबर – महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कलवा में स्थित राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एमबीबीएस प्रशिक्षुओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के मामले में एक प्रोफेसर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. वर्ष 2014 में जब ये घटना हुई तब 63 वर्षीय डॉ. सैलेश्वर नटराजन कॉलेज के सर्जरी विभाग के प्रमुख थे.